DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

हिन्दुस्तान 21 मई 2022 VSPAPERS DATED

बच्चों को दाखिला न देने पर जवाब मांगा

नई दिल्ली, (प्र.सं)। सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूल के सामने बने घर में रहने वाले बच्चों को दाखिल नहीं दिए जाने पर उच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा है। न्यायालय ने इस मामले में डीडीए और स्कूल प्रबंधन को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

न्यायालय ने दो बच्चों की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। बच्चों ने याचिका में दावा किया है कि भूमि आवंटन की शर्तों के अनुसार स्कूल में दाखिला पाने का पहला अधिकार उनका है और इस अधिकार से उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस संजीव नरूला ने अगली सुनवाई 19 जुलाई से पहले जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

DATED – २२-०५-२२

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । 22 मई 2022

बेसमेंट की खुदाई करते समय दीवार गिरी, एक मजदूर की मौत, दो जख्मी

खुदाई के वक्त उसके साथ लगती पहली मंजिल की दीवार ढह गई

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

द्वारका के पोचनपुर गांव के डीडीए फ्लैट्स में बेसमेंट बनाते उससे लगती पहली मंजिल की दीवार गिर गई। इसके नीचे दबने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दो लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस ने मकान मालिक और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

फायर डिपार्टमेंट के अनुसार दोपहर करीब 2.18 बजे सेक्टर-23 पोचनपुर गांव के डीडीए फ्लैट्स से एक बिल्डिंग गिरने की सूचना मिली थी। मौके पर तीन फायर टैंडर भेजे गए। वहां जाकर पता चला कि घर की नींव खोदते समय उससे लगते घर की दीवार गिर गई। इसमें तीन लोग घायल हो गए। घायलों को डीडीयू अस्पताल भिजवाया गया। यहां जगदीश (35) की मौत हो गई, वहीं हरबाई (30) और प्रमोद (10) को मामूली चोटें आईं। डीसीपी द्वारका शंकर चौधरी ने बताया कि मामले की छानबीन के लिए पुलिस टीम को भेजा गया। कॉलर ने बताया था कि डीडीए फ्लैट का लेंटर गिर गया है और उसके नीचे कुछ लोग दब गए हैं। इसके बाद पीसीआर टीम को भेजा गया। वहां जाकर पता चला कि बेसमेंट की खुदाई हो रही थी। इसकी वजह से उसके साथ लगती पहली मंजिल की दीवार ढह गई और इसके नीचे मजदूर दब गए। पुलिस के अनुसार जिस जगह काम चल रहा था वहां के मालिक विरेंद्र सिंह है और इस निर्माण कार्य का कॉन्ट्रैक्टर मिश्री लाल पंडित हैं।

> मालिक और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज

हिन्दुस्तान

दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत

दर्दनाक

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। द्वारका के पोचनपुर गांव में शनिवार दोपहर को एक दीवार गिरने से वहां काम कर रहे मजदूर दंपति और उनका बेटा चपेट में आ गया। हादसे में 40 वर्षीय जगदीश की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और बेटा घायल है।

हादसे की सूचना मिलने के बाद पहुंची द्वारका सेक्टर-23 थाना पुलिस ने जगदीश के शव को कब्जे में लेकर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर मकान के मालिक और ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपायुक्त शंकर चौधरी ने बताया कि मृतक जगदीश अपने परिवार के साथ गोल पार्क द्वारका सेक्टर -24 में रहता था। परिवार में पत्नी 30 वर्षीय हरबाई और 10 वर्षीय बेटा प्रमोद शामिल है। जगदीश और हरबाई ठेकेदार मिस्त्री लाल के पास मजदूरी करते थे। ठेकेदार मिस्त्री लाल ने दोनों को डीडीए फ्लैट पोचनपुर गांव में एक मकान में नींव खोदने के काम पर लगाया गया था। मकान की नींव खोदते समय साथ बने एक पुराने मकान की दीवार गिर गई और जगदीश और उसका परिवार उसके मलबे में नीचे दब गया। लोगों ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद दमकल और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची।

करीब 30 मिनट तक चले राहत कार्य के बाद सभी तीनों लोगों को मलबे से निकाल कर अस्पताल में पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने जगदीश को मृत घोषित कर दिया। जबकि, हरबाई और प्रमोद को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है।

ठेकेदार और मकान मालिक गिरफ्तार

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में केस दर्ज कर ठेकेदार 72 वर्षीय मिस्री लाल और मकान मालिक 50 वर्षीय वीरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया कि मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त को सौंपी गई है। मामले को लेकर 24 घंटे में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

IV दैनिक जागरण नई दिल्ली, 22 मई, 2022

द्वारका के पोचनपुर में दीवार ढहने से कामगार की मौत

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली: द्वारका के पोचनपुर इलाके में एक मकान के बेसमेंट निर्माण के दौरान बगल में स्थित डीडीए फ्लैट की दीवार व छत गिरने से जगदीश की मौत हो गई। वहीं, दस वर्षीय नाबालिग सहित दो लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मकान मालिक व ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हिरासत में ले लिया है। साथ ही निगम को भी नोटिस दिया गया है।

दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शनिवार दोपहर 2.18 बजे मकान ढहने की जानकारी मिली। मौके पर तीन गाड़ियों को भेजा गया। मलबा हटाने के दौरान घायल हरवाई और दस वर्षीय प्रमोद को पहले बाहर निकाला गया। इसके बाद मलबे के बीच में फंसे जगदीश को अग्निशमन कर्मचारियों ने बाहर निकाला। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। छानबीन में पुलिस को पता चला कि द्वारका सेक्टर 17 निवासी विरेंद्र सिंह मकान का निर्माण करा रहा था। मिश्रीलाल पंडित ने मकान बनाने का ठेका लिया था। कामगार मकान की नींव की खुदाई करने के बाद बेसमेंट में दीवार का निर्माण कर रहे थे। इस मकान के बगल में डीडीए का जर्जर फ्लैट है। जगदीश के पिता रघुवीर ने बताया कि वे मूल रूप से टीकमगढ़ मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं। जगदीश अन्य कामगारों के साथ पिछले एक माह से कार्य कर रहा था। शनिवार दोपहर को सभी कामगार खाना खाने के बाद आराम कर रहे थे।

इसी दौरान जर्जर फ्लैट की दीवार व छत ढह गई। इसमें जगदीश मलबे के नीचे दब गए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पहले यह पता लगाया जा रहा है कि इस मकान का निर्माण वैध तरीके से हो रहा था या फिर अवैध तरीके से। निगम अधिकारियों से जानकारी मांगी गई है। निर्माणाधीन मकान व जर्जर इमारत के बारे में फोटो के साथ 28 अप्रैल 2022 को निगम को जानकारी दी गई थी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER दैनिक जागरण नई दिल्ली, 22 मई, 2022 DATED

प्रदूषित हवा सुधार रहे बायोडायवर्सिटी पार्क, गिरता भूजल भी कर रहे रि

अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस

संजीव गुप्ता • नई दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के सातों बायोडायवर्सिटी पार्क लगातार राजधानी की आबोहवा में सुधार कर रहे हैं। इनकी वजह से यहां जीव जंतुओं के अलावा हरित क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है और भूजल स्तर में भी वृद्धि देखने को मिली है। खास बात यह कि इन पार्कों के जरिये बड़ी मात्रा में वर्षा का जल भी बचाया जा रहा है।

दिल्ली में बायोडायवर्सिटी पार्क का कारवां सन 2002 में तत्कालीन डीडीए उपाध्यक्ष और निवर्तमान उपराज्यपाल अनिल बैजल और दिल्ली विश्वविद्यालय के तत्कालीन सम्कुलपति प्रो. सी आर बाबू के प्रयासों से हुआ था। पहला पार्क यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के नाम से शुरू हुआ।

इसके बाद 2005 में अरावली, 2015 में तिलपथ वैली और कमला नेहरू रिज, 2016 में नीला हौज और तुगलकाबाद और 2019 में कालिंदी बायोडायवर्सिटी पार्क की शुरुआत हुई। बंजर और बहुत ही डिग्रेडिड लैंडस्कैप से शुरू हुए ये पार्क पर्याप्त संख्या में वनस्पतियों और जीवों को आश्रय देते हैं। 2016 में यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में एक तेंदुआ भी देखा गया था। वहीं अरावली जैव विविधता पार्क में भारतीय पित्त और काली चील जैसे कई पक्षी लंबे समय के दौरान देखे गए हैं।

अरुणा आसफ अली मार्ग पर स्थित नीला हौज पार्क में ऐतिहासिक झील, जो मलबे और सीवेज के कारण बेकार हो गई थी, उसे वैटलैंड के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया।

असाध्य रोगों का इलाज करने में भी मददगार है पौधे

इन बायोडायवर्सिटी पार्कों ने न केवल प्रदूषित हवा को शुद्ध करने में मदद की, बल्कि भूजल को भी रिचार्ज किया और लाखों गैलन पानी इकट्ठा करने में मदद की। डीडीए अधिकारियों के अनुसार सभी पार्कों द्वारा 2021 में एकत्रित वर्षा जल 1.4 मिलियन गैलन है। वेटलैंड में 1,100 मिलियन गैलन मानसून का और खादर क्षेत्र में संग्रहित 500 मिलियन गैलन बाढ़ का पानी है। करीब 3,000 एकड़ में फैले इन पार्कों से हर साल ढाई लाख छात्र व्यावहारिक पर्यावरण शिक्षा प्राप्त करते हैं। इन पार्कों के विकसित होने के बाद से स्थलीय-जलीय पौधों, चिड़ियों की संख्या भी बढ़ी है। यहां लगे दो हजार से ज्यादा प्रजाति वाले औषधीय पौधे असाध्य रोगों का इलाज करने में भी मददगार है।

बायोडायवर्सिटी सोसायटी व दिल्ली बायोडायवर्सिटी काउंसिल गठित

2019 में उपराज्यपाल ने बायोडायवर्सिटी सोसायटी का गठन किया था, जबकि एक नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने 11 सदस्यीय दिल्ली बायोडायवर्सिटी काउंसिल की अधिसूचना जारी की थी। जल्द ही लोक जैव विविधता पंजी (पीपुल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर-पीबीए) बनाने का काम शुरू होगा।

> बायोडायवर्सिटी पार्कों ने न केवल दुनिया भर के शहरी क्षेत्रों से लुप्त होती प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए माडल के रूप में वैश्विक महत्व ग्रहण किया है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला भी प्रदान की है। शहरों में पानी की उपलब्धता और सांस्कृतिक और संरक्षणात्मक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया है। ये पार्क छात्रों और लोगों के बीच पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रतीक और प्रमुख केंद्र भी बन गए हैं।
>
> -फैयाज ओ खुदसर, प्रभारी, यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क

यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क	2002 वर्ष	2021 वर्ष
सतही पौधे	90	915
जलीय पौधे	00	101
चिड़िया	37	203
तितलियां	11	82
सांप-मेढक	03	18
स्तनधारी जीव	04	22
मछलियां	00	18
अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क	**2005 वर्ष**	**2021 वर्ष**
सतही पौधे	150	950
जलीय पौधे	00	31
चिड़िया	42	219
तितलियां	13	113
सांप-मेढक	08	31
स्तनधारी जीव	05	19
मछलियां	00	00
तिलपथ वैली बायोडायवर्सिटी पार्क	**2015 वर्ष**	**2021 वर्ष**
सतही पौधे	156	481
जलीय पौधे	00	03
चिड़िया	81	125
तितलियां	21	55
सांप-मेढक	14	15
स्तनधारी जीव	05	07
मछलियां	00	00

नेहरू प्लेस इलाके में फायर ब्रिगेड के लिए बने रैंप पर हो रही है पार्किंग

नेहरू प्लेस मार्केट में फायर ब्रिगेड के लिए बनाए गए रैंप पर खड़ी कार • जागरण

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली : नेहरू प्लेस में अतिक्रमण व अवैध पार्किंग के कारण दुकानदार परेशान हैं। यहां पर फायर ब्रिगेड के लिए बनाए गए रैंप पर भी लोग पार्किंग कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि पार्किंग के स्टाफ रैंप पर वाहन पार्क करवा देते हैं। इस कारण लोगों का आवागमन बाधित होता ही है। किसी आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड व एंबुलेंस के जाने के लिए भी जगह नहीं बचती है। दुकानदारों ने इस बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के साथ ही स्थानीय पुलिस से भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

नेहरू प्लेस में 100 से अधिक इमारतें हैं, जिनमें हजारों दुकानें व आफिस हैं, लेकिन यहां पर आग से बचाव के लिए प्राथमिक व्यवस्था भी बदहाल है। इस मार्केट में फायर ब्रिगेड के लिए बनाए गए रैंप पर अतिक्रमण व अवैध पार्किंग के कारण यहां आपात स्थिति में वाहनों का पहुंच पाना मुश्किल हो सकता है। मार्केट एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने बताया कि पार्किंग के ठेकेदार यहां खूब मनमानी करते हैं और शिकायत करने पर दादागिरी पर उतर आते हैं। डीडीए व पुलिस से भी इस बारे में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई राहत नहीं मिली है। मार्केट में रेहड़ी-पटरी वाले दुकानदारों के कारण भी काफी परेशानी हो रही है। बेतरतीब लग रहीं दुकानें व बाडी वेंडर के कारण मार्केट में चलना दुश्वार है। इस अव्यवस्था पर डीडीए का पक्ष जानने के लिए पीआरओ को काल किया गया, लेकिन उन्होंने काल रिसीव नहीं की।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI DATED MAY 22, 2022

14 yrs on, Kathputli Colony residents yet to get homes

NEVER-ENDING WAIT

2,800
Total number of flats being developed for slum dwellers

720
Flats expected to be allotted by September 2022

2,080
Number of flats expected to be allotted by July 2023

37sqm
Approximate size of each flat

One-bedroom flats, with hall, kitchen, toilet, bathroom and balcony

₹1.1 lakh
Amount to be paid by slum dwellers for each flat, apart from ₹30,000 as the maintenance cost

5.2 hectares
Area of the redeveloped colony

3.4 hectares
Area to be used for residential development

677
Total slum clusters in Delhi

490
Total number of slum clusters on DDA and central government land

376
Slum clusters taken up first for identification for in situ slum rehabilitation on PPP mode

3
Number of ongoing projects

10
Slum clusters where work is expected to begin soon

Sidhartha.Roy@timesgroup.com

New Delhi: Fourteen years ago, Delhi Development Authority (DDA) first announced its in situ slum redevelopment project at Kathputli Colony. Since then, the wait for its residents to receive their promised one-bedroom flats in multi-storey apartments has only got longer.

It was expected that the first batch of around 500 flats in the completed apartment blocks would be handed over by March 31, 2022. The rest of the apartments were expected to be allotted by the end of this year. A total of 2,800 one-bedroom flats are to be allotted to slum dwellers in the redevelopment project.

According to DDA officials, the land development authority is now targeting September 2022 for handing over 720 flats to the first batch of residents and the rest of the flats by July 2023.

The tender enquiry for the colony was floated in 2008, and the work was awarded to a private developer in August 2009. As part of the redevelopment project, 2,800 flats in 14-storeys towers would be given to squatters who were living in the area for nearly 40 years. In place of constructing the EWS houses, the developer would be entitled to build and dispose of some freehold HIG flats and commercial built-up area equivalent to 10% of the EWS floor area ratio on a leasehold basis.

The project has been beset with setbacks and massive delays in every step, starting from surveying the eligible population, relocating all the slum dwellers to a transit camp at Anand Parbat and finally, the ongoing construction.

The foundation stone of the project was laid by Union Housing and Urban Affairs minister Hardeep Singh Puri on April 24, 2018. It was announced that the first batch of slum dwellers were expected to be provided flats by March 2019. While the March deadline was missed, DDA hoped to open some towers by December 2019 but that deadline was missed too, with the project facing one roadblock after another, including the work getting affected due to the Covid-19 pandemic.

While relocation of the residents of Kathputli Colony had begun in 2014, all slum dwellers could be moved out only by the end of 2017. Even as the site was finally levelled the following year, power connection to the construction site stopped over pending dues of earlier occupants.

As soon as the issue of the pending bills was sorted, a ban on construction during the winter season again put a halt to work. Apart from this, there were incidents like roads being dug up by another government agency and materials not reaching the site. The project received another setback in 2019 in the shape of a disputed piece of land for which DDA had to go to court.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE SUNDAY EXPRESS, MAY 22.2022 ERS--- * SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI MAY 22, 2022 --DATED---

One killed, 2 injured after wall collapses in Dwarka

New Delhi: A 35-year-old man was killed and two people, including a 10-year-old boy, were injured after a wall collapsed in Dwarka's Sector-23 Saturday, officials said. Fire officials received information at 2.18 pm about the collapse at the DDA flats, they said, adding that three fire-tenders were rushed to the site. Fire officials said work on a nearby plot, where the foundation for a house was being laid, caused the collapse.

Allow compensatory plantation in neighbour states, pleads DDA

New Delhi: The Delhi Development Authority (DDA) has written to the Union environment ministry, requesting it to allow compensatory afforestation (CA) for all projects undertaken in the city in the neighbouring states in view of a scarcity of land in the national capital. The land-owning agency said the ministry should at least relax the guidelines issued under the Forest Conservation Act to allow compensatory afforestation for the projects implemented by the Centre and public sector undertakings (PSUs) on degraded forest land in the neighbouring states.

In its letter, DDA cited paragraph 2.3(v) of chapter 2 of the Handbook of Forest Conservation Act, which says: "In exceptional cases, where non-forest land/degraded forest land, as the case may be, for CA is not available in the same state/Union territory in which the diversion of forest land is proposed, land for CA can be identified in any other state/UT, preferably in a neighbouring state/UT." ΦΠ

SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MAY 22, 2022

At 60-90% survival rate, plantation drives show 'good' result

GROWING NUMBERS

Picture for representation

Third-party audit of plantations conducted by other agencies

Agencies	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
DDA	-	-	90-95%	80-85%	-
North corporation	72.4%	65.8%	Under process	-	-
PWD	67%	65%	68%	-	-
DSIIDC	70%	75%	80%	82%	85%
DMRC	88.9%	90.2%	76.5%		
Environment department	-	-	60%	65%	87%

Source: Forest department

- Third-party audit report of agencies show the survival rate varied from 60% to 90%
- The survival rate of plantation done by the forest department from 2016-17 to 2018-19 was 75%-80%
- A few agencies are yet to begin third-party audit of plantations
- The plantation target for 2022-23 year is 35.4 lakh and plantation will begin from July 1

Priyangi.Agarwal
@timesgroup.com

New Delhi: A third-party audit of plantations undertaken by various authorities has revealed that the survival rate for 2016-17, 2017-18 and 2018-19 varied from 60% to 90%.

While the audit of agencies like Delhi Development Authority (DDA), public works department (PWD), environment department, north corporation and Delhi Metro is over, the exercise is still pending for some, including central PWD, Delhi Jal Board, Northern Railway, south and east corporations, and Delhi Transport Corporation.

According to the forest department, which compiled the third-party audit reports carried out by several agencies, DDA achieved the maximum survival rate at 90-95% in 2018-19. Many authorities managed to achieve a survival rate of 80% and above.

"According to National Afforestation and Eco-development Board of the Union ministry of environment and forest and climate change, the survival rate of 80% and above is 'outstanding', and that of 62% to 80%, 'very good'. The audit reports of plantations done in the past years show good results," a forest official said.

DDA's audit was done by Forest Research Institute (FRI). The other third-party auditors were Mahatma Gandhi Institute for Combating Climate Change, Indian Agricultural Research Institute and Indian Council for Agricultural Research.

OFFICIAL SAYS

The survival rate of plantations done near the Yamuna will be better due to soil quality and water level in comparison to the Ridge, which has a rocky terrain

A few authorities have also been audited for 2019-20 and 2020-21. For the environment department and Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation, the survival rate was 87% and 85%, respectively, in 2020-21. The rate was 67.7% for BSES for 2016-21.

Environment minister Gopal Rai earlier said the survival rate for the forest department was 75-80% for 2016-19, and FRI had been asked to conduct an audit for 2019-20.

The survival rate depends on climatic conditions and biotic stress, said another official. "The survival rate of plantations done near the Yamuna will be better due to soil quality and water level in comparison to the Ridge, which has a rocky terrain. Extreme weather events like excess rain or higher temperature and biotic factors such as human and animal interference also play an important role," the official added.

For 2022-23, the plantation target is 35.4 lakh saplings and the drive will begin from July 1.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

DATED

IV दैनिक जागरण नई दिल्ली, 23 मई, 2022

दिल्ली में भूमि बैंक बनाने की योजना नहीं चढ़ी परवान

डीडीए ने कहा, जब राजधानी में जमीन ही नहीं तो फिर बैंक कैसा

संजीव गुप्ता • नई दिल्ली

देश के अन्य राज्यों की तर्ज पर दिल्ली में भी लैंड (भूमि) बैंक बनाने की योजना सिरे चढ़ने से पहले ही खारिज हो गई है। दरअसल, जमीन की कमी होने से यह बैंक अस्तित्व में ही नहीं आ पाया। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अब इस बैंक की योजना को पूरी तरह से नकार दिया है।

गौरतलब है कि विकास कार्यों के लिए दिल्ली में पेड़ काटना बहुत बार मजबूरी बन जाता है। हालांकि, इस स्थिति में संबंधित एजेंसी की ओर से एक के बदले 10 पेड़ लगाए जाने का प्रविधान है, लेकिन पेड़ लगाने के लिए जगह न मिलना बड़ी समस्या बन जाती है। हरित क्षेत्र के विस्तार में आ रही इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए 2020 में वन विभाग और डीडीए के बीच भूमि बैंक को लेकर सहमति बनी, लेकिन कुछ ही माह में शुरू होने वाला यह बैंक अभी तक वजूद में नहीं आ पाया।

> डीडीए के पास पौधारोपण के लिए कहीं जमीन नहीं बची है। मास्टर प्लान के हिसाब से भी दिल्ली का हरित क्षेत्र तय सीमा से ज्यादा हो चुका है। ऐसे में भूमि बैंक का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। इसी के चलते केंद्र सरकार को पत्र लिखकर पौधारोपण के लिए दिल्ली को पड़ोसी राज्यों में जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
>
> -राजीव तिवारी, प्रधान आयुक्त (उद्यान), दिल्ली विकास प्राधिकरण

वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में भूमि डीडीए के ही पास होती है, लिहाजा डीडीए को हर साल पौधारोपण के लिए एक ही या अलग-अलग जगह खाली जमीन मुहैया करानी थी। जमीन का मालिकाना हक उसी के पास रहना था, जबकि सात साल तक उसका रखरखाव वन विभाग को करना था। किसी भी एजेंसी को पेड़ लगाने के लिए जमीन की जरूरत होती तो उसे वन विभाग से जमीन मिल जाती। वन विभाग संबंधित एजेंसी को उसकी जरूरत के मुताबिक जमीन दे देता। लेकिन दिल्ली की लगातार बढ़ती आबादी और कम होती जमीन के चलते भूमि बैंक की योजना आगे ही नहीं बढ़ सकी। डीडीए का कहना है कि अब उसके पास पौधारोपण के लिए कहीं पर भी जमीन खाली नहीं बची है। छोटे-छोटे टुकड़ों में जो जमीन है वह दिल्लीवासियों की अन्य जरूरतों के लिए है। जैसे, स्कूल, पार्क, सामुदायिक भवन इत्यादि।

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 23 मई 2022

कमला नेहरू रिज में तितलियां होंगी संरक्षित

इंटरनैशनल बायोडायवर्सिटी डे के मौके पर पार्क का उद्घाटन, 63 प्रजातियां देख सकेंगे

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

तितलियों के इस पार्क को खास तौर पर ऐसी जगह बनाया है, जहां बंदर अधिक हैं। इससे बायोडायवर्सिटी मजबूत होगी

इंटरनैशनल बायोडायवर्सिटी डे के मौके पर कमला नेहरू रिज में रविवार को तितलियों को संरक्षित करने वाले पार्क का उद्घाटन किया गया। इस पार्क में तितलियों की 65 प्रजातियों को देखा जा सकता है। इनमें मुख्य तौर पर प्लेन टाइगर, स्ट्रिप्ड टाइगर, कॉमन गुल, पायनियर, रेड पिय्रोट, वाइट ऑरेंज टिप, येलो ऑरेंज टिप आदि हैं। इसके अलावा दुर्लभ प्रजातियों की तितलियों जैसे ग्रेट एगफ्लाइ बटरफ्लाई और रेड पिय्रोट को भी यहां देखा जा सकता है।

रविवार को डीडीए के वाइस चेयरमैन मनीष गुप्ता ने यह पार्क आम लोगों को समर्पित किया। मिली जानकारी के अनुसार, तितलियों के इस पार्क को खास तौर पर ऐसी जगह बनाया गया है, जहां बंदर अधिक हैं। इस मौके पर डीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों, हंसराज कॉलेज के स्टूडेंट्स और सुबह की सैर के लिए आने वाले लोगों ने यहां तितलियों को देखा। बायोडायवर्सिटी पार्क प्रोग्राम के हेड डॉ फैयाज खुदसर ने कहा कि जैव विविधता हमेशा से सस्टेनेबल डिवेलपमेंट के लिए चुनौती रही है और यह स्वास्थ्य के साथ पानी, खाने की जरूरतों के लिए जरूरी है।

राजधानी के सात बायोडायवर्सिटी पार्क ने न सिर्फ लोगों को प्रकृति से जोड़ा है, बल्कि उन्हें जैव विविधता के बारे में बताया भी है। इस मौके पर डीयू के पूर्व प्रो वाइस चांसलर और बायोडायवर्सिटी पार्क के प्रोजेक्ट इंचार्ज प्रफेसर सीआर बाबू ने बताया कि डीडीए के बायोडायवर्सिटी पार्क इस साल इंटरनैशनल डे ऑफ बायोडायवर्सिटी की थीम पर फिट बैठ रहे हैं। इस बार की थीम सभी जीवों के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। डीडीए के प्रिंसिपल कमिश्नर डॉ राजीव तिवारी ने कहा कि शहरों के विकास के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। इसलिए इस समय हमें सुनियोजित विकास पर फोकस करने की जरूरत है। हंसराज कॉलेज की प्रफेसर मोनिका कॉल ने कहा कि बायोडायवर्सिटी पार्क एक जीवित लैब है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAI Hindustan Times NEW DELHI MONDAY MAY 23, 2022 DATED

Butterfly conservatory at Ridge, designed to keep monkeys at bay

Jasjeev Gandhiok
jasjeev.gandhiok@hindustantimes.com

NEW DELHI: On International Biodiversity Day, a butterfly conservatory was inaugurated at the Kamla Nehru Biodiversity Park in north Delhi, uniquely designed to keep out monkeys, which have a strong population in the Northern Ridge.

After measuring the wing span of the largest butterfly in Delhi, the entire conservatory — spread over an area of 672 sqm — has been covered with a wire-mesh based cage, which will allow butterflies to move in and out freely, while preventing monkeys from entering or trampling flowering plants.

Already, 65 different butterfly species have been sighted at the Biodiversity Park, which is run by the Delhi Development Authority (DDA), with the conservatory created in order to increase the count of these butterfly species.

Butterflies at the Kamla Nehru Biodiversity Park. SOURCED

Officials said that among the common sightings are butterflies such as the Plain Tiger, Striped Tiger, Common Gull, Pioneer, White Orange Tip and Yellow Orange Tip, while the rare species include the Great Eggfly Butterfly and the Red Pierrot.

Faiyaz Khudsar, scientist in-charge at the Yamuna Biodiversity Park (YBP) in north Delhi said this set-up allows more such butterfly conservatories to be set up in areas dominated by monkeys, which otherwise make it difficult to grow new plants.

"Normally, the plants would get trampled, or eaten. So, we had to find a solution that allowed butterflies and birds to enter and exit freely, but one that kept out monkeys," said Khudar.

A combination of nectar-bearing plants and host plants have been planted in the conservatory.

"We have also planted some species outside, to attract butterflies towards the conservatory," said Khudsar.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI MONDAY, MAY 23, 2022 ----DATED----

Land Pooling: 3 Yrs After Launch, Work Begins On 3 Model Sectors

Nearly 3L People To Be Accommodated In Initial Leg In North, NW Delhi

Sidhartha.Roy@timesgroup.com

New Delhi: More than three years after its launch, the process has finally begun for developing three 'model' sectors under the Delhi Development Authority's (DDA) land pooling policy. The three sectors, which would come up in north and northwest Delhi, are expected to accommodate a population of about 3 lakh.

The model sectors are Sector 10-A in Zone N, which falls in northwest Delhi, and Sector 2 and 3 in Zone P-II in north Delhi, along the Yamuna river.

DDA had launched a single-window portal where landowners could apply for developing land parcels under the policy in February 2019. Till February 2022, nearly 19,000 acres of land have been submitted for development under the policy but the land parcels are scattered across different areas and not forming a congruous area, making it difficult for DDA to create sectors.

DDA has issued provisional notice for formation of consortium for three sectors under the policy and the validity of the notice is three months.

"Provisional Notice for consortium formation has been issued with a condition that remaining un-pooled landowners have to come together and form contiguous land as a single entity with an Implementation Plan, for which they will get a 90 days period," a DDA spokesperson said. In case, constituent landowners fail to form a consortium or are unable to achieve 70% contiguous pooled land in that sector, such notice will be deemed cancelled or withdrawn, he said. The Land Pooling Policy is currently applicable in the urban extension areas of Delhi, he said. This comprises 104 villages falling in Zones J, K-I, L, N, P-I, and P-II as per Delhi's master plan.

As per applications received on DDA's web portal for inviting expression of willingness, 16 sectors in Zones P-II, N, and L (southwest Delhi) have been identified as priority sectors that have achieved participation or pooling of approximately 70% or more land. "This entire area is divided into 129 sectors and, on an average, each sector is anticipated to accommodate a population of 80,000 to 1 lakh. The policy has received an encouraging response with approximately 7,275 hectares of land submitted as on February 28, 2022 through DDA's web portal," he said.

He said that in some sectors, in spite of having achieved 70% or more participation, there are land parcels in the pooled land that are under multiple ownership, and where all the owners have not expressed their willingness for participation in land pooling. "For facilitating land pooling in such sectors, Provisional Notice is being issued."

WORK IN PROGRESS

3
'Model sectors' to come up first under land pooling policy

104
Villages come under urban extension area of Delhi and where the policy is applicable

129
Sectors planned

16
Priority sectors identified that have achieved participation of pooling of approx 70% or more land

80,000-1 lakh
Approx population each sector is expected to accommodate

7,275 hectares
Land submitted for development till February 28, 2022

THE MODEL SECTORS

Sector 2, Zone P-II

Location | Along the Yamuna in north Delhi. Land parcels in villages Tigipur, Akbarpur Majra, Sungarpur and Baktawarpur

140 hectares
Developable land

121 hectares
Land belonging to owners willing to participate

Sector 3, Zone P-II

Location | Adjacent to Sector 2 in north Delhi. Land parcels in villages Tigipur, Fatehpur Jat, Mohammadpur, Ramjanpur and Baktawarpur

210 hectares
Developable land

56 hectares
Land belonging to owners who have come forward for development

Sector 10-A, Zone N

Location | Near Bawana, northwest Delhi. Land parcel in Bazidpur Thakran village

124 hectares
Developable land

117 hectares
Land that has already been pooled under the policy

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

N. THE INDIAN EXPRESS, MONDAY, MAY 23, 2022 ..... DATED .....

No decision taken on excavations at Qutub Minar, says Culture Minister

DIVYA A
NEW DELHI, MAY 22

AFTER REPORTS emerged on Sunday that the Ministry of Culture has ordered the Archaeological Survey of India (ASI) to conduct excavations at the Qutub Minar in Delhi, officials in the ministry told *The Indian Express* that no such orders have been issued at present. Union Culture Minister G K Reddy also clarified: "No such decision has been taken."

Culture Secretary Govind Mohan visited the monument on Saturday, after which it was reported that the ASI has been ordered to conduct excavations to ascertain whether the UNESCO World Heritage Site was built by Qutubuddin Aibak in the 12th Century or by the Gupta Empire much earlier. The Ministry insisted it was a regular site visit by its officials and no such decision has been taken. ASI officials were not available for comment.

A few days ago, former ASI regional director Dharamveer Sharma was quoted as saying that the Qutub Minar was actually a "sun tower" built by Chandragupta Vikramaditya of the Gupta Empire in the 5th Century.

On Saturday, Mohan had spent over two hours there, along with a team of senior officials and historians, wherein various aspects pertaining to the upkeep of monuments were discussed. In light of a recent letter written by the National Monument Authority to the ASI on moving two Ganesha idols out of the complex, "owing to their disrespectful placement", the team also visited the adjoining Quwwat-ul-Islam mosque, wherein the idols in question are currently placed.

A source privy to the proceedings added that the ASI has been asked to conduct the iconography of idols at Qutub Minar. It has also been recommended that visitors should be given detailed information on various Hindu and Jain idols located in the complex through appropriate signboards. Even though there has been no decision on conducting excavations, the matter did come up for consideration during the official visit, added the source.

Later, the ministry team also visited the 1,000-year-old Anang Tal lake in the vicinity, which is set to be declared a national monument by the ASI. In fact, Delhi Development Authority vice-chairman Mukesh Gupta also visited the water reservoir Saturday, announcing that the lake's cleaning up and beautification will begin as soon as next week. The DDA also plans to remove encroachments from the Anang Tal area, ministry officials said.

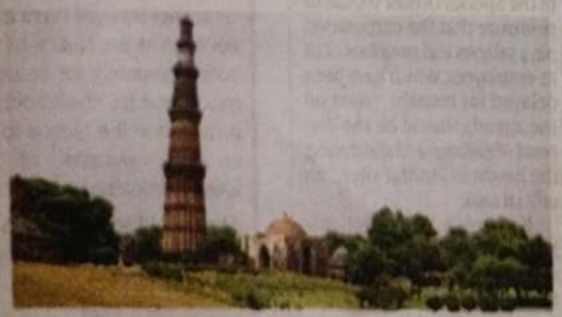

Culture Secretary Govind Mohan visited the monument on Saturday. *Archive*

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MONDAY, MAY 23, 2022

Catch up with butterflies at new address near DU

Priyangi.Agarwal@timesgroup.com

New Delhi: A butterfly conservatory was inaugurated at the Kamla Nehru Ridge for the public on International Biodiversity Day on Sunday. As the Northern Ridge has thousands of monkeys who end up uprooting host and nectar-bearing plants, this conservatory has been fenced with a mesh in a way that butterflies can easily enter.

Spread over 672 square metres, the conservatory has 65 butterfly species, including rare sightings like Great Eggfly Butterfly and Red Pierrot.

The butterfly conservatory was inaugurated by Delhi Development Authority (DDA) vice-chairman Manish Gupta.

The conservatory has been specially designed for monkey-dominated landscapes and for areas where other biotic pressures are rampant, said C R Babu, who is the project incharge of two biodiversity parks — Yamuna and Aravalli.

Faiyaz Khudsar, incharge scientist, Biodiversity Parks Programme, Centre for Environment Management of Degraded Ecosystems (CEMDE), said: "For attracting butterflies, we need to plant host and nectar-bearing plants along with creating a small water body with aquatic plants as butterfly indulge in mud puddling for maturity."

"However, as thousands of monkeys live at the Kamla Nehru Ridge, it becomes difficult for these plants to survive. We considered another method in which caterpillars are grown somewhere else and are later transferred to a fully closed structure but later decided to design the conservatory using the iron wire mesh," he added.

Scientists first studied the area and found big butterfly species like Common Mormon, Common Rose, and lime butterfly, which have wing stands of three-four inches.

"Iron mesh has holes of four inches so that butterflies can easily travel. Even some birds like Common Myna, Bulbul, and Brown-headed barbet enter the enclosure to catch a butterfly and hence the natural process is going on," said Khudsar adding some host plants have also been planted outside the conservatory. Butterflies lay eggs on their host plants, while the caterpillars feed on the leaves of these plants.

Some of the common butterfly species which have been spotted here are Plain Tiger, Striped Tiger, Common Gull, Pioneer, Red Pierrot, White Orange Tip, and Yellow Orange Tip. At Kamla Nehru Ridge, which is located near Delhi University, a team of CMEDE is also restoring two lakes here. To celebrate International Biodiversity Day, senior officials from DDA, students from Hansraj College and other DU colleges, and many morning walkers joined the celebration.

WINGED RESIDENTS: Spread over 672 square metres, the conservatory has 65 butterfly species

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NE THE INDIAN EXPRESS, MONDAY, MAY 23, 2022 DATED

HARDLOOK

The bulldozer gathers pace

Routine anti-encroachment drives in Delhi have taken a political hue ever since one was held in Jahangirpuri, days after communal violence there. Since then, what used to be a bureaucratic process has pitted AAP and BJP firmly against each other

ABHINAV RAJPUT
NEW DELHI, MAY 22

TWO BULLDOZERS were engaged in demolishing a house spread on around two acres in South Delhi's Kalyanpuri last week. Watching from a distance, Shyam Pihal, who lives in a jhuggi cluster adjoining the road, made a phone call to his friend: "MCD wale aaye hain, sab log idher aa jao, kahi ye jhuggi na todne ka sochein (People from the MCD are here, all of you come, they might just think of breaking the jhuggis)."

While the drive was carried out by the Delhi Development Authority (DDA) on court orders, the much publicised anti-encroachment drives carried out across the city by civic bodies have sparked fear in people's minds. The year-round activity has also turned into a flashpoint between the BJP, which has been ruling the MCD for three terms, and the opposition Aam Aadmi Party.

The first big drive

The erstwhile North Delhi Municipal Corporation carried out an anti-encroachment demolition drive in Jahangirpuri on April 20, days after the area witnessed communal violence following a Hanuman Jayanti procession. It was stopped mid-way by the Supreme Court.

While Opposition parties hit out at the BJP for bringing in "bulldozer politics" of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh to Delhi, those in the party as well as a section of people hailed state unit chief Adesh Gupta for "teaching the rioters a lesson".

Gupta had written to the North MCD Mayor demanding identification and demolition of "illegal encroachment" and construction by those arrested in the Jahangirpuri violence. He also ordered the three corporations to undertake more such drives to remove "illegal encroachments by Bangladeshis and Rohingya".

While the AAP was not directly critical of the drive at that point, its MLA Atishi accused the BJP of helping settle Bangladeshis and Rohingya in different parts so that *goondagardi* (hooliganism) can be perpetrated. In the days since, a series of anti-encroachment exercises have been carried out across the capital, and the AAP has become more direct in its opposition to the drives.

Since Jahangirpuri

The MCD has carried out more than 25 drives, with an average of around one per day, in the past one month. These have been in areas such as Jahangirpuri, Dilshad Garden, Dallupura, Geeta Colony, Kanti Nagar, Mangolpuri, Najafgarh, Hari Nagar, Chaukhandi, Vasant Kunj, Raghubar Nagar, Janakpuri and Dwarka. "These drives are conducted based on feedback and the nature of complaints. Most of them are to clear the right of way; there is no pick and choose," said a deputy commissioner in the North MCD.

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, meanwhile, has asked his party MLAs to hit the ground against these drives and show their support for people.

On May 9, South MCD officials tried to carry out an anti-encroachment drive in Shaheen Bagh but were stopped by residents and representatives of the Congress and AAP, who protested in front of the bulldozer. Three days later at Madanpur Khadar, the civic body barricaded the street and started tearing down the walls of four under construction buildings that were allegedly being constructed illegally. Clashes broke out between locals and police and AAP MLA Amanatullah Khan was arrested. During DDA's drive in Kalyanpuri, AAP MLA Kuldeep Kumar was detained by police.

According to data from the Special Task Force constituted by the MoHUA in April 2018 to clear encroachments and unauthorised constructions in the capital, the corporations along with other government agencies have removed 4,132 encroachments till April 15. As many as 4,319 properties have been demolished while there is a pendency of 7,522 cases.

A deputy commissioner with the South MCD admitted that the drives have intensified in the past one month, but attributed it to several complaints that had piled up over the past two years due to the pandemic and inability of the civic body to act on the same.

Earlier, he said, councillors too used to resist such drives as it went against popular sentiments. "Now they themselves are taking the lead, making our work easier."

Some discontent

Not all within the BJP are enthusiastic about this. Two MPs that *The Indian Express* spoke to said the drive had started to backfire and the party should not associate itself with it as it is carried out by bureaucrats on a routine basis.

"This is not the Uttar Pradesh model. Yogi ji carries out these drives on criminals; here it is being done locality wise. While the Jahangirpuri drive was to send a message to rioters, what are we gaining by associating with the drives in Dwarka, Matiala, New Friends Colony?" said an MP.

Another senior BJP leader said, "In the past, we have confronted the MCD during the sealing drives... our MP even broke the seal of a shop. Now, it feels like we are getting carried away by the media hype... Now that the special officer (of the unified MCD) has taken charge, he should undertake a course correction and stop such drives. Or the party should make it clear that it does not back them."

Former Puducherry chief secretary Ashwani Kumar has been appointed as the Special Officer of the unified MCD, and took charge Sunday.

A senior BJP leader, who is also office bearer in the state team, said, "We should have disassociated ourselves after Jahangirpuri... or Shaheen Bagh."

The BJP has now started to slowly distance itself from the drives. Gupta said, "We back only those drives where the mafia has encroached common land. The rest are routine exercises by the MCD and the BJP has nothing to do with it."

The AAP, meanwhile, blamed the BJP for targeting the common man. While Kejriwal said that the BJP and MCD had put the lives and livelihoods of 63 lakh people, who live in unauthorised areas, in danger, AAP leader Saurabh Bhardwaj said at a recent press conference, "The BJP is targeting the poor and middle class... It has planned encroachment drives in Saket P block, Qutub Institutional Area, Chirag Delhi — do Rohingya live here? I stay in Chirag Delhi, where Jats and Brahmins live."

For and against

It has largely been traders, jhuggi clusters and roadside vendors who are bearing the brunt of such drives. Lakshmi, who lives in a jhuggi in Trilokpuri, said she has been living in the area for the past 10 years along with her family of six. Though the MCD has not reached the locality, the fear remains. "Yeh todenge to hum kahan jayenge (where will we go if they break our home?). My husband drives an e-rickshaw and my son lost his job during the pandemic; he worked in an office in Noida... We do not earn enough that we can pay rent."

About one-third of Delhi lives in substandard housing, which includes 695 slums and JJ clusters, 1,797 unauthorised colonies, and 362 villages. Among them, those living in slums and JJ clusters lack access to basic facilities like toilets and sewer connections.

Residents, meanwhile, said the corporation should focus on more pressing issues like sanitation. B S Vohra, who heads the East Delhi RWA Joint Front, said the corporation should widen roads rather than focusing on cosmetic actions: "Areas like Krishna Nagar see bad traffic snarls, causing pollution."

At Shaheen Bagh, Shahazad Ali, who owns a furniture shop, said the garbage in the area is rarely cleared and the corporation should focus on this. Another resident of the area, Itteshan Azmi, said these encroachments would be back in a few days: "The bigger question is how these encroachments came up in the first place."

Mayor Mukesh Suryan, however, said, "Ask people if they are relieved that encroachments have been cleared..."

A deputy commissioner in the South MCD added, "Encroachment is done by poor people, but the rich will not be spared — if their houses are on government land, they too will be demolished."

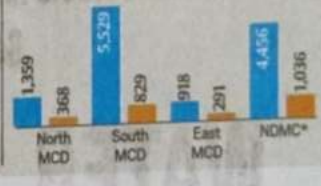

During the drive in Jahangirpuri last month. *Archive*

ANTI-ENCROACHMENT AND DEMOLITION DRIVES

ACTION TAKEN BY CIVIC BODIES

Agencies	Complaints*	Structures demolished	Sealed	Items seized
North MCD	57,346	1,628	395	1,063
South MCD	43,298	1,922	1,821	1,592
East MCD	17,245	494	367	607

(*Till April 30, 2022)

Data: Special Task Force created by MoHUA
*New Delhi Municipal Council

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEW[SPAPER] राष्ट्रीय सहारा नई दिल्ली। रविवार • 22 मई • 2022 [DAT]ED

राजधानी में वनीकरण के लिए उपलब्ध नहीं है जमीन

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखकर दिल्ली में वनीकरण को लेकर जमीन की कमी होने की बात कही है। साथ ही सुझाव दिया है कि सरकार को इसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत जारी दिशा-निर्देशों में ढील देनी चाहिए, जिससे पड़ोसी राज्यों में निम्नीकृत वन भूमि पर केंद्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं के लिए प्रतिपूरक वनीकरण की अनुमति दी जा सके। डीडीए का कहना है कि राजधानी में 1990 के बाद से भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ है।

डीडीए को अब मास्टर प्लान के तहत चिह्नित किए गए हरित क्षेत्रों में से प्रतिपूरक वनरोपण के लिए भूमि की आवश्यकता को पूरा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि डीडीए ने मंत्रालय को लिखे अपने पत्र में कहा गया है कि यदि उस राज्य-केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिपूरक वनीकरण उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, जहां कि वन भूमि के उपयोग में बदलाव प्रस्तावित है, तो प्रतिपूरक वनीकरण के लिए किसी अन्य राज्य-केंद्र शासित प्रदेश की भूमि की पहचान की जा सकती है।

1990 के बाद दिल्ली में अधिग्रहण प्रक्रिया है बंद

डीडीए ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को लिखा पत्र

हो सके तो इसके लिए पड़ोसी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में ही भूमि की पहचान की जाए। डीडीए ने कहा है कि मंत्रालय पड़ोसी राज्यों दिल्ली में वन भूमि पर केंद्र /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा क्रियान्वित परियोजना के लिए सीए की अनुमति देने पर विचार कर सकता है। प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के मास्टर प्लान के तहत मनोरंजन के लिए अधिग्रहित भूमि उपयोग के लिए 15 प्रतिशत क्षेत्र को अलग रखने का निर्णय लिया गया है, इसके तहत सभी पार्क, हरित पट्टी और जंगलों का रखरखाव किया जाता है। उन्होंने वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा प्रकाशित नवीनतम वन रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि मनोरंजक हरित उपयोग के लिए पहचाने गए 15 प्रतिशत क्षेत्र के मुकाबले, राजधानी में वन और वृक्षों का आवरण अब 23 प्रतिशत से अधिक है। डीडीए ने पत्र में लिखा है कि मास्टर प्लान के तहत चिह्नित किए गए अधिकांश मनोरंजक हरित क्षेत्र पहले से ही वृक्षों से भरे पड़े हुए हैं। दिल्ली के नागरिकों की बुनियादी विकास संबंधी जरूरतों के लिए छोटे टुकड़ों में उपलब्ध अन्य खाली भूमि आवश्यक है।

पंजाब केसरी

भूमि की कमी पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को लिखा पत्र

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): प्रतिपूरक पौधारोपण के लिए डीडीए ने दिल्ली सरकार को जमीन उपलब्ध कराने में हाथ खड़े कर दिए हैं। मुख्य सचिव को दो बार पत्र लिखने के बाद डीडीए ने अब केंद्रीय पर्यावरण सचिव को भी एक पत्र लिखकर सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। डीडीए दिल्ली के संदर्भ में द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के दिशा निर्देशों में बदलाव करने भी आग्रह किया है। साथ ही यह भी कह दिया है कि अब अगर पौधारोपण के लिए और जमीन दी जाएगी तो फिर दिल्ली से जुड़ी विकास परियोजनाओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। डीडीए उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता की ओर से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन की सचिव लीना नंदन को पत्र लिखकर कहा गया है कि जमीन की कमी होने के कारण द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत प्रतिपूरक पौधारोपण के लिए भूमि उपलब्ध कराना मुश्किल हो गया है। मास्टर प्लान के तहत जो 15 प्रतिशत क्षेत्र इस उद्देश्य के निमित्त रखा गया है, वह भी 20 प्रतिशत तक पौधारोपण से भर चुका है।

बिंदापुर में पानी-सीवर लाइन बदलना शुरू

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र के बिंदापुर डीडीए के फ्लैट में रहने वाले लोगों को जल्द गंदे पानी और सीवर की समस्या से निजात मिल जाएगी। लोगों की समस्या को दूर करने के लिए उत्तम नगर से आप विधायक नरेश बाल्यान ने बिन्दा पुर डीडीए के फ्लैट में 40 साल पुरानी पानी और सीवर की लाइनों को बदलवाने के लिए नई लाइनों को डालने का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली का विकास हो रहा है। सालों से जिन काम के लिए क्षेत्र के निवासी परेशान थे उसे आप सरकार दूर कर रही थी। उन्होंने कहा कि यहां 40 साल पुरानी पाइप लाइन थी जिस कारण लोग परेशान हो रहे थे, लोगों की इन समस्या को दूर करने के लिए पाइप लाइन बदलने का काम शुरू हो गया है, जल्द ही यह समस्या दूर हो जाएगी। हमारी कोशिश है कि बरसात के दौरान यहां जलभराव की समस्या न हो। इस मौके पर पूर्व निगम पार्षद देश राज राठौर, आप नेता सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

अमर उजाला

पड़ोसी राज्यों से वन क्षेत्र विकसित करने का अनुरोध

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से डीडीए ने दिल्ली में भूमि की कमी को देखते हुए पड़ोसी राज्यों के शहर में शुरू की गई सभी योजनाओं के लिए पौधरोपण की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

डीडीए ने मंत्रालय से कहा है कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत जारी दिशा-निर्देशों में ढील देनी चाहिए ताकि पड़ोसी राज्यों में वन क्षेत्र को पर्यावरण के लिए और बेहतर किया जा सके। डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार दिल्ली के मास्टर प्लान के तहत मनोरंजन भूमि उपयोग के लिए 15 प्रतिशत क्षेत्र को अलग करने का निर्णय लिया है। ब्यूरो

DELHI DEVELOPMENT
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------- DATED- 23/5/2022

पंजाब केसरी 23/5/2022

कमला नेहरू रिज पार्क में बटरफ्लाई कंजरवेटरी शुरू

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): राजधानी के कमला नेहरू रिज में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान तितली संरक्षिका (बटरफ्लाई कंजरवेटरी) का उद्घाटन किया गया। समारोह में डीडीए के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कि तितलियों को बंदर समेत अन्य जानवरों से बचाने के लिए संरक्षिका के आसपास लोहे का जाल बनाया गया है। जैव विविधता पार्कों के ये जंगल दिल्ली के लिए जीवन रेखा बन रहे हैं। टिकाऊ भविष्य के लिए हमें खपत कम करने और जैव विविधता पार्कों की स्थापना में अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। जैव विविधता पार्क कार्यक्रम के प्रभारी वैज्ञानिक फैयाज ए खुदसर के मुताबिक यह संरक्षिका अपनी तरह की अनूठी पहल है। यहां कुल करीब 65 प्रजातियों की तितलियां हैं। इनमें प्लेन टाइगर, स्ट्राइप्ड टाइगर, कॉमन गुल, पायनियर, रेड पियरोट, व्हाइट ऑरेंज टिप, येलो ऑरेंज टिप आदि अन्य कुछ दुर्लभ प्रजाति की तितलियां जैसे ग्रेट एगफ्लाई बटरफ्लाई, लाल पायरोट आदि शामिल हैं।

अमर उजाला

मकान की दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत

दस साल के बालक समेत दो घायल

नई दिल्ली। द्वारका के पोचनपुर इलाके में एक मकान के बेसमेंट के निर्माण कार्य के दौरान पड़ोस में स्थित डीडीए फ्लैट की दीवार गिर गई। हादसे में मलबे में दबकर वहां काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दस साल का एक लड़का सहित दो घायल हो गए।

मौके पर पहुंचे बचाव और राहत दल ने घायलों को मलबे से निकाल कर पास के अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मकान मालिक और ठेकेदार को हिरासत में ले लिया है। दमकल अधिकारियों ने बताया कि शनिवार दोपहर दमकल विभाग और पुलिस को पोचनपुर में एक मकान की दीवार के ढहने और उसमें कुछ लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली। मौके पर दमकल की तीन गाड़ियां और पुलिसकर्मी पहुंच गए। ब्यूरो

अमर उजाला 23/5/2022

मन मोह लेंगी रंग-बिरंगी तितलियां

डीडीए के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने किया तितली संरक्षिका उद्यान का लोकार्पण

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। राजधानी के कमला नेहरू रिज में रविवार को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान डीडीए के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने तितली संरक्षिका व उद्यान का लोकार्पण किया। उनके साथ पर्यावरणविद् प्रो. सीआर बाबू व जैव विविधता पार्क कार्यक्रम के प्रभारी वैज्ञानिक डॉ. फैयाज खुदसर मौजूद रहे।

मुख्य अतिथि मनीष गुप्ता ने कहा कि जैव विविधता पार्क दिल्ली के लिए जीवन रेखा बन रहे हैं। टिकाऊ भविष्य के लिए हमें खपत कम करने और जैव विविधता पार्कों में अधिक निवेश करने की जरूरत है। कमला रिज पार्क में कुल 65 प्रजाति की तितलियों का संरक्षण किया गया है। इसमें प्लेन टाइगर, स्ट्राइप्ड टाइगर, कॉमन गुल, पायनियर, रेड पियरोट, व्हाइट ऑरेंज टिप, येलो ऑरेंज टिप आदि और यहां पाई जाने वाली दुर्लभ प्रजातियां ग्रेट एगफ्लाई बटरफ्लाई और रेड पियरोट भी शामिल हैं।

तितली संरक्षिका व उद्यान का लोकार्पण करते डीडीए अध्यक्ष। अमर उजाला

उद्यान में तितली।

डॉ. फैयाज ए खुदसर ने कहा कि प्रकृति जलवायु, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, भोजन और पानी तक विकास की चुनौतियां, सुरक्षा और सतत आजीविका का जवाब है। जैव विविधता ही नींव है। सात जैव विविधता का नेटवर्क दिल्ली में पार्क एक ऐसी पहल है, जहां ऐसी कई चुनौतियों का जवाब हकीकत में आया है।

प्रोफेसर सीआर बाबू ने कहा कि इस साल जैव विविधता दिवस की थीम सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण बहुत सटीक रखी गई है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जलवायु अनुकूल शहर बनाने के लिए अधिक जैव विविधता पार्कों की स्थापना होनी चाहिए। डीडीए के प्रधान आयुक्त डॉ. राजीव तिवारी ने कहा कि शहरों के विकास के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- millenniumpost NEW DELHI | SUNDAY, 22 MAY, 2022 ATED-

DDA TO UNION ENVIRONMENT MINISTRY

Land scarcity in Delhi, allow compensatory afforestation in neighbouring states: DDA

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) has written to the Union environment ministry, requesting it to allow compensatory afforestation for all projects undertaken in the city in the neighbouring states in view of a scarcity of land in the national Capital.

The land-owning agency said the ministry should at least relax the guidelines issued under the Forest Conservation Act to allow compensatory afforestation for the projects implemented by the Centre and public sector undertakings (PSUs) on degraded forest land in the neighbouring states.

In its letter to the ministry, the DDA cited paragraph 2.3(v) of chapter 2 of the Handbook of Forest Conservation Act, which says: "In exceptional cases, where non-forest land/degraded forest land, as the case may be, for CA is not available in the same state/Union territory in which the diversion of forest land is proposed, land for CA can be identified in any other state/UT, preferably in a neighbouring state/UT."

"It is proposed that para 2.3(v) of the guidelines issued by the ministry may in general be relaxed for Delhi and CA may be allowed in neighbouring states," the letter written by the DDA to the ministry read.

According to the guidelines issued under the Forest Conservation Act, compensatory afforestation is to be carried out on suitable non-forest land, equivalent to the area proposed for diversion, at the cost of the user agency.

Compensatory afforestation can also be carried out on degraded land, twice in extent of the forest area diverted, in case of the projects implemented by the Centre or PSUs.

"The ministry may consider allowing CA for the project implemented by the central government/PSUs on degraded forest land in the neighbouring states of Delhi," the DDA said.

A senior DDA official said under the Master Plan of Delhi, it was decided to set aside 15 per cent of the area for recreational land use under which all parks, green belts and forests are maintained. "Against the 15 per cent area identified for recreational green use, the total forest and tree cover in the capital is now over 23 per cent as per the latest State of Forest Report published by the Forest Survey of India, Dehradun," he said.

"Most of the recreational green areas identified under the master plan are already saturated with plantations... Other vacant land parcels available in small patches are required for basic developmental needs of the citizens of Delhi," read the DDA letter.

1 killed, 2 hurt after wall collapses in Dwarka: Officials

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: A 35-year-old man was killed and two people, including a 10-year-old boy, were injured after a wall collapsed in the Dwarka Sector-23 area on Saturday, officials said.

Fire officials received information at 2.18 pm about the wall collapse at the DDA flats, Pochanpur, Dwarka Sector-23 B-block, they said, adding that three fire-tenders were rushed to the site.

While digging the foundation for a house, the wall of an adjacent house collapsed, injuring three people, the fire officials said.

The injured were rushed to the Deen Dayal Upadhyay (DDU) hospital in a PCR van.

The deceased was identified as Jagdish (35) and the two injured people were Harbai (30) and Pramod (10), the officials said.

According to police, a caller informed them about the incident and said some people were trapped under the rubble.

A police team reached the spot and found a labourer got buried, a senior police officer said.

Legal action will be taken against Virender Singh (50) of Sector-17 Dwarka, the owner of the plot where the digging was going on, as well as the Mishri Lal Pandit (72) of Vikas Vihar, the contractor for the job, the police said.

Highlights

- Fire officials received information at 2.18 pm about the wall collapse at the DDA flats, Pochanpur, Dwarka Sector-23 B-block, they said, adding that three fire-tenders were rushed to the site
- While digging the foundation for a house, the wall of an adjacent house collapsed, injuring three people
- The deceased was identified as Jagdish (35) and the two injured people were Harbai (30) and Pramod (10), the officials said

— THE HINDU
SUNDAY, MAY 22, 2022

One killed, 2 injured in Dwarka wall collapse

STAFF REPORTER
NEW DELHI

A person was killed and two sustained injuries after a building wall collapsed in Dwarka on Saturday.

Delhi Fire Service (DFS) Director Atul Garg said they received a call at 2.18 p.m. after which three fire tenders were sent to B-Block in Dwarka's Sector 23.

While digging the foundation for a house, the wall of an adjacent building collapsed, leaving three injured. They were identified as Jagdish, 35, Harbai, 30, and Pramod, 10. They were rushed to Deen Dayal Upadhyay Hospital where Jagdish succumbed to his injuries.

DCP (Dwarka) Shankar Choudhary said it was revealed that during construction of the basement, a portion of a DDA flat collapsed. A few labourers were also trapped under the debris.

Legal action will be taken against Virender Singh, the owner of the plot where the digging was going on, as well as Mishri Lal Pandit, 72, the contractor, the police said.

Fire incidents

Multiple fire incidents were reported in the city on Saturday. A fire [illegible] new Parliament [illegible] factory in north Delhi's [illegible] wana and [illegible] Delhi's Pandav Nagar area.

Another fire incident [illegible] reported at a furniture [illegible] in a market [illegible] wa. However, no casualties were reported. According to the DFS, the blaze [illegible] brought under control [illegible] short period.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

SMOULDERING EMBERS

Triggered by the scorching heat this year, major fire incidents have witnessed an increase — leading to huge loss of life and property; strict implementation of existing laws could prevent similar mishaps in future

NARESH BISWANI

> "DFS is just a technical department, hence, the entire responsibility goes to the building authorities as they are aware of the new constructions. Not to the fire department."
> — Atul Garg

> "The police take stringent actions under appropriate legal sections if the owner or the authority does not seek NOC or other required documents."
> — Suman Nalwa

A total of 591 people died in fire incidents in 2021-22 whereas 346 people died in 2020-21